JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

19 वीं सदी के भारत में राजनीतिक संगठनों की राष्ट्रीय आन्दोलन में भूमिका

डॉ. शिच चरण चेड़वाल
सहायक आचार्य इतिहास
बाबू शोभाराम राजकीय महाविद्यालय अलवर

प्रस्तावना. राजनीतिक संगठनों ने 19 वीं शताब्दी के भारत का परिचय आधुनिक राजनीति से कराया। धर्म अथवा जाति प्रधान संगठन इस देश में पहले भी विद्यमान थेए परन्तु इन नये संगठनों की स्थापना ऐसे व्यक्तियों ने की जिनकी एकता का आधार धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य थे। सामान्य प्रशिक्षणए सामान्य शिक्षाए सामान्य महत्वकांक्षाएं तथा ब्रिटिश राज्य के प्रति असन्तोष आदि शक्तियों ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया था।

मुख्य शब्द - राजनीतिक संगठनए राष्ट्रवादए पाश्चात्य संस्कृतिए राजनीतिक आन्दोलनए ईस्ट इण्डिया कम्पनीए बॉम्बे प्रेसिडेन्सी

पाश्चात्य संस्कृति का भारत पर एक प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि इस देश में राष्ट्रीयताए राष्ट्रवाद तथा राजनीतिक अधिकारों आदि आधुनिक राजनीतिक विचारों का विकास हुआ। भारतीय उपमहादीप में ऐसे राजनीतिक विचारों तथा संगठनों का जन्म हुआ जिनके अस्तित्व से अब तक भारतीय अनभिज्ञ थे।

भारतीय राजनीतिक आन्दोलन के मार्गदशर्क राजाराम मोहन राय 31 थे जिन्होंने भारत वासियों की शिकायतों की ओर अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया। अक्टूबर 1851 में ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन नामक एक नया राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ। इसे लैण्डहोल्डर्स तथा बंगाल ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी दोनों का ही सहयोग प्राप्त था। आर.सी. मजूमदार के अनुसार ये दोनों संस्थायें ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन में विलीन हो गयी द्य 32 देवेन्द्रनाथ टैगोर इस संस्थान के सचिव थे तथा राधाकांत देव संस्थान के अध्यक्ष चुने गये द्य

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के चार्टर के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश संसद के लिए यह आवश्यक था कि वह भारत में हो रही गतिविधियों का लेखा- जोखा अपने सम्मुख रखे । अतएव भारतीय राजनीतिक संगठनों के लिए आवश्यक हो गया कि वे ब्रिटिश संसद को इस सन्दर्भ में प्रभावित करने के लिए याचिकाएं भेजें। इस कारण इस समय प्रेसिडेन्सी नगरों में राजनीतिक सरगरमी प्रारम्भ हुई। परिणामस्वरूप कलकत्ते में 1851 में ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन स्थापित हुआ तथा 1852 में बम्बई तथा मद्रास में भी संगठन स्थापित हुए।

ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन ने ब्रिटिश संसद को एक याचिका भेजी जिसमें मांग की गई कि बंगाल के लिए एक लोकतांत्रिक विधानसभा स्थापित कीजाएए उच्च अधिकारियों का वेतन कम किया जाएए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए तथा नमक पर कर एवं आबकारी व स्टैम्प कर को समाप्त किया जाए। इन मांगों की पूर्ति आंशिक रूप से अवश्य हुई क्योंकि 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार गर्वनर जनरल की कौंसिल के सदस्यों कीए वैधानिक कार्यों के लिए संख्या में छरू की वृद्धि की गई। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को बुरी प्रकार झकझोर दिया था ।

1858 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर विचार किया। सर सैयद अहमद खां ने ब्रिटिश सरकार को समझाया कि विधानसभाओं में भारतीयों को प्रतिनिधित्व न देनाए ब्रिटिश सरकार तथा भारतीयों के मध्य गलतफहमी का प्रमुख कारण है। सर बार्टल फ्रेरे ने भी इस कथन का समर्थन किया।

इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों ही देशों में जनमत इस पक्ष में था कि भारत को किसी न किसी रूप में प्रतिनिधि संस्थाऐं प्रदान की जायें। किन्तु इस दिशा में कार्यवाही की गति बहुत मन्द थी।

1870 तक भारतीय समाज में परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे। प्रेसिडेन्सी नगरों में उच्च शिक्षा भली प्रकार स्थापित हो चुकी थी तथा नए व्यवसायों में लगे हुए लोग समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे। यह प्रवृत्ति एक अखिल भारतीय आन्दोलन के जन्म के लिए उत्साहवर्धक थी।

कलकत्ता में दो नए संगठन स्थापित किए गए तथा योजना के अनुसार देश भर में इनकी शाखाएं स्थापित की जानी थी । देशवासियों में देश प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से 1875 में एसण केण घोष ने इण्डियन लीग की स्थापना की। यह संकुचित दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन को एक चुनौती थी। लीग का वार्षिक चन्दा केवल पांच रूपये निर्धारित किया गया जबकि ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन द्वारा निर्धारित राशि पचास रूपये थी। एसण केण घोष ने अमृत बाजार पत्रिका में लिखाए श्देश के हित में इन दोनों संगठनों को प्रतिस्पर्द्धा करने दीजिए।श लीग में मध्य वर्ग का ही नहीं वरन् सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व था। थोड़े ही समय पश्चात् जुलाईए 1876 में लीग का विलय इण्डियन एसोसिएशन नामक संगठन में हो गया जिसकी स्थापना सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा आनन्द मोहन बोस ने की 1 34 इसके उद्देश्य लीग के लक्ष्यों के समान ही थे । बनर्जी के अनुसार इण्डियन एसोसिएशन के निम्न उद्देश्य थे।

;1द्ध देश में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना ।

;2द्ध समान हितों तथा आकांक्षाओं के आधार पर भारतीय जातियों तथा लोगों का एकीकरण।

;3द्ध हिन्दुओं तथा मुसलमानों के मध्य सद्भावना तथा मैत्री को बढ़ावा देना।

;4द्ध समस्त जनसमुदाय को बड़े जन आन्दोलनों में सम्मिलित करना द्य

इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना के साथ बंगाल के विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय हो गये। उन्होंने 1875 में ही अपने संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए थे। बम्बई में 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन का गठन हुआ। इसका उद्देश्य बॉम्बे प्रेसिडेन्सी में रहने वाले भारतीय लोगों की भावनाओं का पता लगाना तथा जन कल्याण के लिए शासन को उचित उपाय सुझाना था। एसोसिएशन ने मांग की कि विधानसभाओं में भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसने इस तथ्य की भर्त्सना की कि उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्ति नहीं किया जाताए जबकि सरकार कार्य रहित उच्च पदों पर यूरोपियन लोगों को नियुक्त कर उन पर धन का भारी अपव्यय करती है । 1868 में इसने प्रशासनिक सेवा के प्रश्न पर एक विज्ञापन भेजा तथा 1869 में मांग की कि प्रशासनिक सेवा के लिए इंग्लैण्ड तथा भारत में एक साथ परीक्षा ली जाए।

बॉम्बे प्रेसिडेन्सी की राजनीति की विशेषता यह थी कि यहां पारसियोंए गुजरातियों तथा मराठों ने राजनीतिक क्षेत्र में एक होकर कार्य किया। आमतौर पर पारसी समाज सरकार के प्रति वफादार थी। लार्ड लिटन के अनुसार पारसी लोग ब्रिटेन की रानी के प्रजाजनों में सबसे अधिक वफादार थी।

सन् 1867 में जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे द्वारा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। गणेश वासुदेव जोशी ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रानाडे के अनुसार भारत की समृद्धि औद्योगिक क्रांति के अभाव में असम्भव थी। 37 सभा ने भारतीय जनता में अधिकारों की चेतना जागृत की तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु संवैधानिक साधनों पर बल दिया। 1876.77 के अकाल में सभा द्वारा अनेक प्रकार से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई गई। सभा ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के विरूद्ध आवाज उठाईए इल्बर्ट बिल 1883 के विरोध में आन्दोलन चलाया और स्थानीय स्वशासन की मांग की। लेजिस्लेटिव कौंसिलों के सुधार तथा सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति हेतु भी सभा द्वारा मांग की गई। इसके अतिरिक्त सभा कृषकों की समस्या उठाने तथा इन्हें दूर करने में अधिकतम व्यस्त रही।

1852 में स्थापित मद्रास नेटिव एसोसिएशन 38 कलकत्ता के ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन की ही एक शाखा थी। कम्पनी के चार्टर के नवीनीकरण के समय 1853 कलकत्ता में तथा बम्बई के एसोसिएशनों की भांति मद्रास एसोसिएशन ने भी एक याचिका ब्रिटिश संसद को भेजी थी जिसमें लगभग वे ही मांगे थीं जो कि कलकत्ता तथा बम्बई के संघों ने की थी। ए.सी. मजूमदार ; एक भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्षद्ध के अनुसार मद्रास नेटिव एसोसिएशन का कार्य कुछ अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। मद्रास के जनसाधरण पर इसका प्रभाव नगण्य था। फिर भी मद्रास नेटिव एसोसिएशन किसी प्रकार

1868 तक चलता रहा।

लंदन में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों फिरोजशाह मेहताए बदरूद्दीन तैयबजीए मनमोहन घोषए दादाभाई नोरोजी इत्यादि ने 1865 में लंदन इण्डियन सोसाइटी की स्थापना की। भारतीयों की शिकायतें दूर करने तथा अंग्रेजी प्रेस में भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार को ठीक करने का कार्य इस संगठन के माध्यम से किया गया। अक्टूबर सन् 1866 को दादाभाई नोरोजी ने ईस्ट इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना की । ष इसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी जनता तथा संसद सदस्यों के समक्ष भारत संबंधी विषयों पर समस्त सूचना प्रस्तुत करना था। शीघ्र ही एसोसिएशन ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और 1869 में इसकी शाखाऐं बम्बईए कलकत्ता तथा मद्रास में खोली गई। एसोसिएशन व्दारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्धए अफगान युद्ध के खर्च वहन न करने तथा कपास ड्यूटी समाप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किये गये थे।

ईस्ट इण्डियन एसोसिएशन के अतिरिक्त लंदन में कुछ अन्य संगठनों की भी स्थापना हुई। 1867 में मैरी कारपेन्टर द्वारा नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1872 में आनन्द मोहन बोस ने इण्डियन सोसाइटी की स्थापना की।

उल्लेखनीय है कि ये सभी संस्थाएं क्षेत्रीय थी या प्रान्तीय अथवा देश के बाहर बनाई संस्थाएं थी। अतः शीघ्र ही भारतीयों को यह अनुभव होने लगा कि अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था का होना आवश्यक है। अतः 1885 ईण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।

भारत में काफी समय से ऐसी राजनीतिक संस्थाओं का अभाव महसूस किया जा रहा थाए जो समस्याओं को सरकार के समक्ष स्पष्ट रूप से रख सके। किन्तु उस समय तक कोई ऐसी संस्था नहीं थीए जो राष्ट्रीय स्तर की हो तथा जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत हो । तत्कालीन भारतीय नेताओं का यह विश्वास था कि समस्या का समाधान प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा सम्भव नहीं है। अतः सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के प्रयत्नों 1883 ई. में प्रथम भारतीय कांफ्रेंस का अधिवेशन हुआए किन्तु शीघ्र ही इस संस्था के स्थान पर 1885 ईण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जो अत्यन्त ही लोकप्रिय प्रमाणित हुई। यहां उल्लेखनीय है कि 1885 ईण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना न तो एक आकस्मिक घटना थी और न ही एक ऐतिहासिक दुर्घटना यह उस राजनीतिक चेतना की प्रक्रिया की चरम सीमा थी जो 1860 व 1870 के दशकों में प्रारंभ हुई थी। कांग्रेस की स्थापना इसे बढ़ती चेतना की पराकाष्ठा थी ।

इस संस्था को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने का कार्य एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एण ओण ह्यूम को सौंपा गया। इसी कारण एण ओण ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता माना जाता है। डब्लूए सीण बनर्जी आदि अनेक भारतीय नेताओं का विचार था कि एण ओण ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श से की है ताकि भारत में व्याप्त असन्तोष को विद्रोह के रूप में परिणत होने से बचाया जा सके। लाला लाजपत राय ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए यंग इण्डिया में लिखाए ष्भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि ह्यूम अंग्रेजी साम्राज्य को छिन्न.भिन्न होने से बचाना चाहते थे।ष इसके विपरीत गुरुमुख निहालसिंह ने लिखा हैए ष्यह सम्भव है कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने तथा कांग्रेस का प्रयोग एक अभय दीप की तरह करने के विचार ह्यूम तथा बेडरवर्न के हृदयों में होंए किन्तु इस बात पर विश्वास करना असम्भव है कि दादाभाई नौरोजीए सुरेन्द्रनाथ बनर्जीए व्योमेश चन्द्र बनर्जीए फिरोजशाह मेहता और रानाडे जैसे भारतीय नेता इनके हाथों में साधन मात्र थे या वे भी ब्रिटिश साम्राज्य को क्रांति के खतरे से बचाने का विचार रखते थे । ष

आधुनिक शोधकार्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि एण ओण ह्यूम एक उदारवादी व्यक्ति थे तथा भारत में समाज सुधार करना चाहते थे। भारतीयों की स्थितिए निर्धनता व कष्टों को देखकर उनके मन में भारतीयों के प्रति सहानुभूति थी। ह्यूम का विचार था कि भारतीयों की यह समस्याएं तभी दूर हो सकती है। जबकि वे राजनीतिक रूप से संगठित हों तथा कोई ऐसी संस्था हो जो सरकार तक जनसाधारण की समस्याओं को पहुंचा सके।

इस विषय में जकारिया ने लिखा हैए ष्लोकतन्त्रवादी भारतीय एवं अंग्रेज समर्थकों के संयुक्त प्रयत्नों से इस महान राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ। इस कार्य में उन्हें प्रेरणा संकीर्ण भावों से नहीं वरन् सत्य और न्याय के विचारों के प्रति सच्ची लगन और भक्ति से मिली । ष

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की स्थापना किए जाने के समय यह मूलतरू एक सामाजिक संस्था थी न कि एक राजनीतिक संस्था । अतः राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग सम्भव न था । इस बात की पुष्टि डब्लूण सीण बनर्जी के उस वक्तव्य से भी होती है जो उन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दिया था उन्होंने अपने वक्तव्य में कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्यों मेंए राष्ट्रवादियों में परस्पर सौहार्द बढ़ानाए पारस्परिक वैमनस्य

समाप्त कर एकता को बढ़ावा देनाए महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करना आदि शामिल थे। अतः स्पष्ट हो जाता है कि अपनी स्थापना के समय कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य सामाजिक थे न कि राजनीतिक । किन्तु कुछ समय बाद ही कांग्रेस के उद्देश्य राजनीतिक हुए थे।

ए. ओ॰ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना चाहे किसी भी उद्देश्य से की होए किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसकी स्थापना के अत्यन्त दूरगामी राजनीतिक परिणाम हुएए व भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारम्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाज में व्याप्त कुरीतियों व सरकारी नीतियों से उत्पन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने वाली एक संस्था थी। किन्तु शनैः–शनैः इसका स्वरूप परिवर्तित होता चला गया और यह शीघ्र ही एक राजनीतिक संस्था बन गयी। इस प्रकार सन् 1885 में कांग्रेस की स्थापना से भारतीय इतिहास में एक नये अध्याय का शुभारम्भ होता है। इस संस्था ने भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा अन्त में उन्हें राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कराई।

कांग्रेस की स्थापना से आगामी लगभग 20 वर्षो तक भारत का राजनीतिक आंदोलन शांतिपूर्ण और वैद्यानिक ढंग से चलता रहा। कांग्रेस की राजनीति के इस चरण में राजनीतिक आन्दोलन के लिये
मुख्यतः उदारवादी मार्ग अपनाया गया। अपने अस्तित्व के प्रथम दो दशकों में कांग्रेस पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के प्रभाव में थी। लोग साम्राज्यवादी संस्कृति की उपज थे और चाहते थे कि औपनिवेशिक शासन बना रहे। अतएव कांग्रेस केवल कुछ रियायतें मांगती थी न कि देश के लिए स्वशासन।

यद्यपि सर्वोच्च तथा प्रांतीय विधान परिषदों के विस्तार तथा सुधारए इनमें भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व अन्य प्रान्तों के लिए विधान परिषदों के गठनए इन परिषदों की कार्यक्षमता में विस्तार इत्यादि की मांग तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से ही प्रारम्भ हो गई थी और इसके उपरान्त लगभग सभी अध्यक्षीय भाषणों में दोहराई गई थी। कांग्रेस की वास्तविक जीवित प्रतिनिधित्व की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। सेवाओं के भारतीयकरण की मांगए कांग्रेस की एक अन्य महत्वपूर्ण मांग थी। 1885 की कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस ने मांग की थी कि जनपद सेवा के लिए प्रतियोगिता इंग्लैण्ड तथा भारत में एक ही समय होनी चाहिए ताकिए अधिक भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग ले सके। कालान्तर में कामन्स सभा ने कांग्रेस की इस मांग के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित तो कर दिया परन्तु इसे इस विचाराधीन काल में कार्यान्वित नहीं किया गया।

यूरोपीय प्रबोध तथा उदारवाद की भावना से प्रेरित ये नरमदल के लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा विधि के शासन की मांग करते थे। उन्होंने कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका के कार्यों के अलग.अलग करने की मांग की तथा निवारक बन्दीकरण कानून को रद्द करने की मांग की। 13 1886 के अधिवेशन में कांग्रेस ने इन सभी सुधारों कीए सर्वव्यापी समर्थन के आधार परए पुनरू मांग की और फिर यह मांग हर वर्ष दोहराते चले गए। कांग्रेस के नेताओं ने इस बात पर भी बल दिया कि प्राथमिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए।

मुख्य रूप से अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण कांग्रेस के नेताए विशेषकर पुरानी पीढी के लोगए अंग्रेजी इतिहास तथा संस्कृति की बहुत सराहना करते थे और प्रायरू भारत के अंग्रेजी सम्बन्धों को ष्दैवी कृपा ष कहते थे। यह उनका मूलभूत विश्वास था कि अंग्रेजी राज्य भारत के हित में था इसलिए वे अंग्रेजी को शत्रु नहीं मित्र मानते थे। वे विश्वास करते थे कि समय पाकर अंग्रेज उन्हें पाश्चात्य परम्परा के सर्वोत्तम मानदण्डों के अनुसार स्वशासन के योग्य बना देगा। 1886 में कांग्रेस प्रधान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज के वरदानों का मुक्त कष्ट से गुणगान किया।

कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष श्री बदरूद्दीन तैयबजी ने कहा श्महामहिम की करोड़ों की प्रजा में भारतीय शिक्षित वर्ग से अधिक राजभक्त तथा अंग्रे साम्राज्य से अधिक अनुरक्तए कोई नहीं।ष अतएव ये नरमदल के लोग ऐसा कुछ भी करने को उग्रत नहीं थेए जिससे साम्राज्य निर्बल हो। क्राउन के प्रति राजभक्ति उनका परम विश्वास था और सभी उनके राजनीतिक धर्म की एक महत्वपूर्ण धारा थी।

कांग्रेस के इस नरम रूख तथा दृढ़ राजभक्ति के होते हुए भी उसे सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। आरम्भ में सरकार तटस्थ थी । इसी भावना से प्रेरित होकर लार्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ;1886द्ध के प्रतिनिधियों को एक उद्यानभोज भी दिया था। इसमें यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया कि निमंत्रण कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नहीं अपितु कलकत्ता आए हुए विशिष्ट दर्शकों को है। 1887 में मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के लिए मद्रास नगर में सुविधाएं प्रदान कीए परन्तु 1887 के पश्चात् सरकार का रूख कठोर होता चला गया।

कांग्रेस ने एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसका शीर्षक था एक तमिल कांग्रेस प्रश्नोत्तररूपी शिक्षा जिस में एक मौलवी फरुकुद्दीन तथा कम्ब्रतपुर के रामबख्श के बीच एक वार्तालाप था जिसमें तानाशाही सरकार तथा अनुपस्थित भूस्वामित्व की निन्दा की गई थी और इससे सरकार के साथ खुला विरोध हो गया। अधिकारी वर्ग ने सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिवप्रसाद को प्रेरणा दी कि वे कांग्रेस के प्रचार का प्रतिरोध करने के लिए एक संगठित भारतीय देशभक्त मण्डल का गठन करें। 1888 ई॰ में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के लिए स्थान ही उपलब्ध न होने देनाए कांग्रेस को धन देने वालों पर निगरानी रखना आदि सरकारी नीति के अंग बन गये द्य 44 डफरिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को भी चुनौती दी और कहा कि यह तो केवल एक ‟सूक्ष्मदर्शी अल्प संख्या‟ का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस की मांग तो केवल ‟अज्ञात में छलांग ‟ मारने के समान है। इस समय तक सरकारी सेवकों की कांग्रेस में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं रही। लाई कर्जन ने यह तक कह दिया था ‟कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर जा रही है। ‟ कर्जन की एक अन्य महत्वाकांक्षा यह थी कि वह ‟इसकी शान्तिमय मृत्यु में सहायता कर सके।‟

यद्यपि यह सत्य है कि कांग्रेस आन्दोलन का सामाजिक आधार उन दिनों केवल नगरों में मध्यम वर्ग तक ही सीमित थाए नगरों के औद्योगिक कार्य करने वाले अभी उनके प्रभाव . क्षेत्र से बाहर थे तथा कांग्रेस का संदेश ग्रामों तक पहुंचा ही नहीं था दूसरी ओर मार्क्सवादी विद्वानों ने यह भी कहा है कि नरमदल के नेताओं का दृष्टिकोण बूर्जवा था और वे यह चाहते थे कि भारत का विकास भी बूर्जवा पद्यति के अनुसार ही हो । किन्तु 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादंबिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। 45 यह इस बात का प्रतीक था कि भारत का स्वाधीनता संग्राम स्त्रियों को उस पतित अवस्था से उबारेगा जिसमें वे सदियों के कालक्रम में पहुंचा दी गई थी।

परन्तु दादा भाई नौरोजीए सर फिरोजशाह मेहताए सर दीन शाह वाचाए गोपाल कृष्ण गोखले तथा सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी जैसे लोगों के प्रति न्याय करते हुए हमें यह कहना होगा कि ये लोग उस समय भारतीय समाज में सबसे प्रगतिवादी तत्व थे और वे सच्चे देशभक्त थे। वे मन से यह चाहते थे कि भारतीय समाज का कल्याण हो और उनका यह प्रयत्न रहा कि अंग्रेजी शासन की कठोरता कम की जा सके। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करवाई जिससे लोगों में निराशा हुई और दूसरे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित करवाया जिससे संविधान में आधारभूत परिवर्तन नहीं हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत. सा आरम्भिक कार्य भी किया।

उन्होंने जनता में एक विशाल राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की ओर लोग यह समझने लगे कि वे एक ही राष्ट्र अर्थात भारतीय राष्ट्र के सदस्य हैं। उन्होंने यह भावना भी जगाई की भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रमें राजनीतिक आन्दोलन करने का प्रशिक्षण दिया और जनता में राजनीतिक प्रौढ़ता जाग्रत की।

सम्भवतरू नरमदल के नेताओं की देश के प्रति सबसे बड़ी यह सेवा थी कि उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक आर्थिक प्रभाव लोगों को समझाया। उन्होंने जनता का ध्यान भारतीय निर्धनता की ओर दिलाया और लोगों को यह बताया कि यह निर्धनता मुख्य रूप से ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक साधनों के साम्राज्यीय शोषण के कारण ही है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. मंसएए ।दपसरू जीम म्उमतहमदबम व िप्दकपंद छंजपवदंसपेउरू ब्वउचमजपजपवद ंदक ब्वससंइवतंजपवद पद जीम संजमत 19जी बमदजनतलए टवस.ए ब्ंउइतपकहम न्दपअमतेपजल चतमेए सवदकवदए 1961ए
2. लूणियाए वी. एन. भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकासए लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशनए आगराए वर्ष 1964ए
3. गुप्तए शिवकुमारए आधुनिक भारत का इतिहासए पंचशील प्रकाशनए जयपुरए प्रथम संस्करणए वर्ष 1999ए
4. गौतमए पी.एल.ए आधुनिक भारत ;1757.1947द्ध राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमीए जयपुरए वर्ष 1998ए
5. ग्रोवरए बी॰ एल॰ और यशपालए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकासए एस॰ चंद एण्ड कंपनी लिमिटेडए नई दिल्लीए 2003ए
6. ठंदमतरममए ैनतमदकतंदंजीरू । छंजपवद पद डंापदहए व्गवितक न्दपअमतेपजल च्तमेेए स्वदकवदए ल्मंत 1925ए
7. मित्तलए डॉ॰ ए॰ के॰ए भारत का इतिहास ;1740.1950 तकद्ध साहित्य भवन पब्लिकेशन आगराए 2004ए
8. त्ंदकमए ड।ळरू ैचममबीमे वद प्दकपंद म्बवदवउपबेए च्नइसपेीमत ळण्।ण् छंजमेंद – बवउचंदलए डंकतंेए ल्मंत 1906ए

9. गुप्तए शिवकुमारए आधुनिक भारत का इतिहासए पंचशील प्रकाशनए जयपुरए प्रथम संस्करणए वर्ष 1999ए
10. गौतमए पी.एल.ए आधुनिक भारत ;1757.1947द्ध राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमीए जयपुरए वर्ष 1998ए
11. चंद्रए विपिनए भारत का स्वतंत्रता संघर्षए हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालयए दिल्ली विश्वविद्यालयए दिल्लीए वर्ष 2011ए
12. त्पए संसं संरचंजरू । बंसस जव लवनदह पदकपंए चनइसपेीमत ˆ ण ळंदमेींद ंदक बवउचंदलए लमंत 1920ए उंकतें
13. सिंहए गुरुमुख निहालए भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकासए आत्माराम एण्ड संस ;1600. 1919द्धए दिल्ली 1961ए
14. ग्रोवरए बीण एलण और यशपालए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकासए एसण चंद एण्ड पनी लिमिटेडए नई दिल्लीए 2003ए
15. जैनए डॉण एम.एस.ए आधुनिक भारत का इतिहासए मेकमिलन कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेडए नयी दिल्लीए ;प्रथम संस्करणद्धए वर्ष 1975ए
16. चन्द्रए विपिन आधुनिक भारत का इतिहासए ओरियेंट ब्लैक्स्वॉन प्राण लिमिटेडए दिल्लीए वर्ष 2011ए
17.